RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 10 MARCH TO 16 MARCH 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 06 ■ अंक 29 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

लगातार 11वें दिन पेट्रोल-डीजल में शांति 1 साल में करीब 21 रुपये महंगा हुआ पेट्रोल Page 2

विद्युत सुरक्षा सप्ताह में ली उपकरणों के सदैव उपयोग की शपथ Page 4

5 जी के लिए ज्यादा इंतजार नहीं, तीन महीने में लग सकता है नेटवर्क Page 7

editoria!

कारोबार की नेता स्त्रियां

जानी-मानी अकाउंटिंग फर्म ग्रैंट थॉर्नटन की ओर से बिजनेस लीडरशिप के मामले में महिलाओं की स्थिति पर जारी की गई ताजा सालाना रिपोर्ट पहली नजर में जरूर राहत देने वाली है। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं को लीडरशिप रोल देने के मामले में भारतीय उद्योग जगत फिलिपींस और साउथ अफ्रीका के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया है। यहां सीनियर मैनेजमेंट में महिलाओं का प्रतिशत 39 है जो वैश्विक औसत (31 फीसदी) से कहीं अधिक है। निश्चित रूप से यह तथ्य भारतीय कॉरपोरेट जगत की अच्छी तस्वीर पेश करता है, हालांकि यह बदलाव हाल के वर्षों की देन है। ग्रैंट थॉर्नटन की ही 2015 की सर्वे रिपोर्ट में इस पहलू से भारत की स्थिति खासी कमजोर नजर आती है। उस साल बिजनेस लीडरशिप रोल में महिलाओं का प्रतिशत हमारे यहां महज 15 दर्ज किया गया था और सूची में भारत को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया था। 14 फीसदी के साथ जर्मनी और 8 फीसदी के साथ जापान ही उससे नीचे थे। अगर इन पांच वर्षों में बिजनेस जगत में महिलाओं की स्थिति में ऐसा जबर्दस्त अंतर आया है तो यह यूं ही नहीं हो गया होगा। इसके पीछे सोचे-समझे प्रयासों की बड़ी भूमिका है। हालांकि यह बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में महिलाओं को शामिल करने जैसा औपचारिक मामला नहीं है। सीईओ, एमडी, सीओओ और सीएफओ जैसे महत्वपूर्ण पद कोरी प्रतिष्ठा की चीज नहीं हैं। इन पर बैठे व्यक्ति की योग्यता से कंपनी का प्रदर्शन प्रभावित होता है। बावजूद इसके, कॉरपोरेट जगत में महिलाओं की बेहतर स्थिति को अगर हम भारतीय समाज में महिलाओं की हकीकत से जोड़ लेंगे तो गलती करेंगे। समाज की तो छोड़िए, देश के कुल वेतनभोगी कार्यबल में भी महिलाओं की स्थिति पर नजर डाली जाए तो वह दिनोंदिन पहले से कमजोर ही होती नजर आ रही है। भारतीय थिंक टैंक सीएमआईई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी) की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी (यूएफएलपी) 2019-20 में मात्र 9.7 फीसदी थी, जो अप्रैल 2020 में और कम 7.35 फीसदी दर्ज की गई जबकि नवंबर 2020 तक आते-आते यह उससे भी घटकर 6.9 फीसदी हो गई। इसका मतलब साफ है कि लॉकडाउन का खामियाजा महिला कर्मचारियों को पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा भुगतना पड़ा है। इससे कंपनी प्रबंधन की नजर में महिला कर्मचारियों की हैसियत का अंदाजा मिलता है। समाज में एक इंसान के रूप में भी महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने की जो शुरुआत संसद में महिला आरक्षण विधेयक लाए जाने और फिर 2012 के निर्भया कांड की प्रतिक्रिया में उभरे जनांदोलनों से हुई थी, वह प्रक्रिया भी इधर तेजी से पीछे छूटती नजर आ रही है। यौन उत्पीड़न की घटनाओं को लिया जाए या उनपर शासन तथा समाज की प्रतिक्रिया को या फिर न्यायपालिका से आने वाले फैसलों को, हर स्तर पर चीजें स्त्री हितों के खिलाफ ही जा रही हैं। ऐसे में बिजनेस लीडरशिप रोल से जुड़े इन आंकड़ों पर बहुत ज्यादा खुश होने की गुंजाइश नहीं है।

भारत घटाएगा सऊदी अरब से तेल आयात

ऊर्जा के दूसरे विकल्पों पर तेजी से काम कर रही सरकार

नई दिल्ली। एजेंसी

सऊदी अरब से तेल की आपूर्ति पर लगाम लगाने के लिए भारत अपने पास मौजूद कच्चे स्त्रोत में विविधता लाने और वैकल्पिक ऊर्जा को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वैसे भी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश भारत अरब देशों पर निर्भरता कम करने की पहले से ही कोशिश कर रहा है। भारत ने बीते 5 साल में अमेरिकी तेल का आयात 0.5 फीसदी बढ़ाकर कुल 6 फीसदी कर लिया है। यह बात हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के चेयरमेन कुमार सुराणा ने चर्चा में कही। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार तेल निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) तथा अन्य देशों से कच्चे तेल के उत्पादन पर लागू प्रतिबंधों को उठाने व दाम स्थिर रखने के वादे को पूरा करने का आग्रह कर रहे है।

इससे पिछले सप्ताह सऊदी अरब और रूस के प्रभुत्व वाले गठबंधन ने उत्पादन स्थिर रखने का फैसला किया। सऊदी में तेल कंपनी पर सोमवार को हुए हमले के बाद कच्चे तेल के दाम सालभर के सर्वोच्च स्तर 71 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गए। सुराणा ने कहा कि ऊंची कीमतें कमोडिटी के रूप में तेल के भविष्य को और अधिक नुकसानदायक बनाती है। यह लोगों को ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक संसाधनों की तलाश करने के लिए भी प्रेरित करती है। वे मानते है कि भारत 50 से 60 डॉलर प्रति बैरल की सीमा तक मिलने वाले तेल को खरीदना ज्यादा पसंद करेगा। सरकारी आकड़ों के अनुसार करीब 86 प्रतिशत भारतीय तेल ओपेक सदस्य देशों से लिया गया। जिसमें साऊदी अरब से आने वाला तेल 19 प्रतिशत था। सुराना ने कहा कि भारतीय रिफाइनर तेल बाजार में ईरान के संभावित पुन प्रवेश को देख रहे है। तेल के ऊंचे दामों से ऊर्जा के स्वच्छ स्त्रोतों के लिए भारत के और अधिक प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था भारत 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा का 40 प्रतिशत नवीकरणीय स्त्रोतों से उत्पादन करने लगेगा। भारत ने 2019-20 में अपनी कुल जरूरत का 85 प्रतिशत तेल, 53 प्रतिशत प्राकृतिक गैस का आयात किया था। ' पीएम ने कहा कि अब देश ऊर्जा आयात पर निर्भरता को कम करने पर ध्यान दे रहा है। ब्रेंट ऑयल की कीमतों में इस साल अब तक 30 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है। इससे ईंधन की घरेलू मांग पर काफी बुरा असर पड़ा है। वहीं, कच?चे तेल की ऊंची दरों के कारण भारत के सामने 1950 के बाद सबसे बुरी मंदी का खतरा मंडराने लगा है। सुराणा ने कहा ऊंची कीमतें मुद्रास्फीति को बढ़ाती है और यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है।

संसद ने माध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी

नयी दिल्ली। राज्यसभा ने बुधवार को माध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें भारत को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की बात कही गई है। उच्च सदन ने हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। सदन में उस समय कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्य किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कराए जाने की मांग कर रहे थे। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर हुयी चर्चा का जवाब देते हुए विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मामलों में उनकी सरकार का सख्त रुख है और वह ईमानदारी से भारत को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का केंद्र बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि देश के करदाताओं के पैसों का दुरूपयोग नहीं हो। दुनिया में मध्यस्थता के कई मामले चल रहे हैं और सरकार भारत को भ्रष्ट तरीके से प्राप्त किये गए पंचाट अवार्ड का केंद्र नहीं बनने दे सकती। विधेयक में संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने और भारत को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की बात कही गई है। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि प्रतिष्ठित मध्यस्थों को आकर्षित करके भारत को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिये अधिनियम की आठवीं अनुसूची को खत्म करना आवश्यक समझा गया। इसके अनुसार उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 का और संशोधन करना आवश्यक हो गया। संसद सत्र में नहीं था और तत्काल उस अधिनियम में और संशोधन करना जरूरी हो गया था। ऐसे में 4 नवंबर 2020 को माध्यस्थम और सुलह संशोधन अध्यादेश 2020 को लागू किया गया था। वर्तमान विधेयक कानून बनने के बाद उपरोक्त अध्यादेश का स्थान लेगा।

ओपेक पर तेल निर्भरता घटाएगा भारत, गुयाना से खरीद की तैयारी

नयी दिल्ली। एजेंसी

तेल निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) व रूस सहित अन्य सहयोगियों के तेल उत्पादन में कटौती जारी रखने के फैसले के बाद भारत रणनीति में बदलाव करेगा। सरकार ने तेल कंपनियों से ओपेक व मध्यपूर्व देशों पर निर्भरता घटाने के लिए कहा है।

अभी मध्यपूर्व देशों से आता है कुल खपत का 60 प्रतिशत तेल

भारत अपनी कुल जरूरत का 84 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें 60 प्रतिशत मध्यपूर्व देशों से आता है। सरकारी कंपनियां तेल खरीद में विविधता लाने के लिए गुयाना से करार पर विचार कर रही हैं। सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने रूस के साथ अनुबंधों की समीक्षा की बात कही है। दरअसल, मध्यपूर्व देशों से आने वाला कच्चा तेल पश्चिमी देशों की तुलना में सस्ता पड़ता है। इराक और सऊदी अरब भारत के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता हैं। पिछले सप्ताह सऊदी अरब सहित कई देशों ने तेल उत्पादन बढ़ाने से इनकार कर दिया था।

लगातार 11वें दिन पेट्रोल-डीजल में शांति 1 साल में करीब 21 रुपये महंगा हुआ पेट्रोल

नई दिल्ली। एजेंसी

पेट्रोल-डीजल की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तर पर हैं, लेकिन बीते 11 दिनों से शांति है। हालांकि सरकार भी अब मानने लगी है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम करने के लिए कुछ करने की जरूरत है, ये बात अलग है कि साल भर में पेट्रोल 21 रुपये तक महंगा हो चुका है। लगातार 11वां दिन है जब पेट्रोल डीजल के दाम शांत हैं। हालांकि ये शांति क्यों है ये समझ से परे है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें 65 डॉलर के ऊपर पहुंच चुकी हैं और धीरे धीरे 70 डॉलर की ओर बढ़ रही हैं। ओपेक देशों ने भी भारत के उत्पादन में कटौती कम करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ऐसे में घरेलू बाजार में तेल की कीमतें कम होने के कोई आसार नजर नहीं आते।

आखिरी बार 27 फरवरी को बढ़े थे दाम

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आखिरी बार बदलाव 27 फरवरी 2021 को हुआ था, जब दिल्ली में पेट्रोल के दाम 24 पैसे बढ़े थे और डीजल 15 पैसे महंगा हुआ था। लगातार 11 दिनों से पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर हैं, बावजूद इसके कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर हैं. दिल्ली में पेट्रोल 91 रुपये को पार कर चुका है. ऐसे ही दाम बढ़ते रहे तो मुंबई में पेट्रोल का रेट कुछ दिनों में 100 रुपये पहुंच जाएगा, अभी यहां पेट्रोल 97.57 रुपये प्रति लीटर है. दिल्ली में सबसे महंगा डीजल पिछले साल जुलाई के आखिरी हफ्ते में बिका था, तब भाव 81.94 रुपये प्रति लीटर थे और पेट्रोल का रेट 80.43 रुपये प्रति लीटर था। यानी उस वक्त पेट्रोल से महंगा डीजल बिका था।

दो राज्यों में पेट्रोल 101 रुपये के पार

फरवरी में दो राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश में पेट्रोल ने 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर लिया था। राजस्थान के श्री गंगानगर में आज भी पेट्रोल 101.84 रुपये है जो कि देश में सबसे महंगा है, जबकि डीजल 93.77 रुपये प्रति लीटर है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल 101.59 रुपये प्रति लीटर है और डीजल 91.97 रुपये प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है।

बीते 11 दिनों से पेट्रोल-डीजल में शांति

दिल्ली में भी पेट्रोल 91.17 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है। जो कि एक नया रिकॉर्ड है. मुंबई में भी पेट्रोल 97.47 रुपये प्रति लीटर पर है, कोलकाता में पेट्रोल 91.35 रुपये है. चेन्नई में पेट्रोल का भाव बीते 11 दिनों से 93.11 रुपये प्रति लीटर है।

2021 में पेट्रोल-डीजल में लगी आग

फरवरी में अब तक पेट्रोल-डीजल के रेट में 16 बार बढ़ोतरी हुई है। 1 फरवरी को दिल्ली पेट्रोल का रेट 86.30 रुपये प्रति लीटर था, तब से लेकर अबतक दाम 4.87 रुपये तक बढ़ चुके हैं। इससे पहले जनवरी में रेट 10 बार बढ़े थे। इस दौरान पेट्रोल की कीमत में 2.59 रुपए और डीजल में 2.61 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। साल 2021 में अब तक तेल की कीमतें 26 दिन बढ़ाईं गई हैं। इस दौरान पेट्रोल 7.46 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। 1 जनवरी को पेट्रोल का भाव 83.71 रुपये था, आज 91.17 रुपये प्रति लीटर है। इसी तरह दिल्ली में 1 जनवरी से लेकर आज तक डीजल 7.60 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। 1 जनवरी को दिल्ली में डीजल का दाम 73.87 रुपये प्रति लीटर था, आज 81.47 रुपये है।

1 साल में पेट्रोल करीब 21 रुपये महंगा हुआ

अगर आज की कीमतों की तुलना ठीक साल भर पहले की कीमतों से करें तो 10 मार्च 2020 को दिल्ली में पेट्रोल का रेट 70.29 रुपये प्रति लीटर था, यानी

साल भर में पेट्रोल 20.88 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। डीजल भी 10 मार्च 2020 को 63.01 रुपये प्रति लीटर था, यानी डीजल भी साल भर में 18.46 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। पेट्रोल के बाद डीजल की कीमतें भी महंगाई के नए आसमान पर पहुंच चुकी हैं. मुंबई में डीजल 88.60 रुपये प्रति लीटर है, जो कि अबतक सबसे महंगा रेट है। दिल्ली में डीजल 81.47 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में डीजल 84.35 रुपये प्रति लीटर है, चेन्नई में डीजल का रेट 86.45 रुपये प्रति लीटर है।

क्यों बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम

वजह नंबर 1- पेट्रोल डीजल की कीमतें बेलगाम क्यों हैं, इसके पीछे एक तर्क है कि अक्टूबर से लेकर अबतक कच्चे तेल का भाव 50 परसेंट बढ़कर 66.3 डॉलर के पार चला गया है। इस साल अब तक कच्चा तेल 24 परसेंट तक महंगा हो गया है। क्योंकि दुनियाभर में आर्थिक गतिविधियों में अच्छी तरक्की दिख रही है। हालांकि ये पूरी वजह नहीं है, क्योंकि पिछले साल जनवरी में कच्चे तेल की कीमतें आज से काफी कम थीं, बावजूद इसके लोगों को पेट्रोल डीजल महंगा मिल रहा था।

वजह नंबर 2- पेट्रोल डीजल महंगा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है केंद्र और राज्य सरकारों का टैक्स है। 2020 की शुरुआत में पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 19.98 रुपये थी, जो अब बढ़ाकर 32.98 रुपये कर दी गई है। इसी तरह डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 15.83 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 31.83 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।

वजह नंबर 3- केंद्र के अलावा राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल-डीजल पर ₹ बढ़ाया है। दिल्ली सरकार ने ही पेट्रोल पर ₹ 27 परसेंट से बढ़ाकर 30 परसेंट कर दिया है। जबकि डीजल पर ₹ मई में 16.75 परसेंट से बढ़ाकर 30 परसेंट कर दिया था, लेकिन जुलाई में फिर इसे घटाकर 16.75 परसेंट कर दिया था। पेट्रोल का बेस प्राइस 31.82 रुपये प्रति लीटर है, ऐसे में केंद्र और राज्यों का टैक्स मिलाकर देखा जाए तो वो बेस प्राइस से 180 परसेंट के करीब टैक्स लेती हैं। इसी तरह सरकारें डीजल के बेस प्राइस से 141 परसेंट टैक्स वसूल रही हैं।

2008 में कच्चा तेल 147 डॉलर पर था, पेट्रोल 45 रुपये पर

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 66 डॉलर प्रति बैरल हैं, तब पेट्रोल 100 रुपये के पार बिक रहा है, लेकिन ये तर्क तब फेल हो जाता है जब इसकी तुलना साल 2008 के कच्चे तेल के रेट से करते हैं। कच्चा तेल 2008 में 147 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया था, तब पेट्रोल का रेट 45 रुपये प्रति लीटर था।

कमजोर मांग से कच्चातेल वायदा कीमतों में गिरावट

नयी दिल्ली। एजेंसी

कमजोर हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को घटाया जिससे वायदा बाजार में कच्चा तेल की कीमत बुधवार को 1.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,629 रुपये प्रति बैरल रह गयी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में मार्च महीने में डिलिवरी वाले कच्चा तेल अनुबंध की कीमत 51 रुपये यानी 1.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,629 रुपये प्रति बैरल रह गयी। इसमें 4,868 लॉट के लिये कारोबार हुआ। वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड का भाव 0.95 प्रतिशत की गिरावट के साथ 63.40 डॉलर प्रति बैरल चल रहा था जबकि ब्रेंट क्रूड का भाव 1.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 66.76 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर था।

गुजरात ने दो साल में औद्योगिक इकाइयों का 1,715 करोड़ रुपये का बिजली शुल्क माफ किया

अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने पिछले दो साल के दौरान 16,000 औद्योगिक इकाइयों का 1,715 करोड़ रुपये का बिजली शुल्क माफ किया है। राज्य के ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल ने मंगलवार को विधानसभा को यह जानकारी दी। पटेल ने कहा कि इस कदम का मकसद राज्य में निवेश करने वाली नई औद्योगिक इकाइयों का वित्तीय बोझ कम करना है। उन्होंने कहा कि यदि मौजूदा विनिर्माण इकाइयां विस्तार कर रही हैं, तो बिजली शुल्क माफी का लाभ उन्हें भी दिया जाएगा। उन्होंने लिखित जवाब में कहा कि यह शुल्क माफी गुजरात बिजली शुल्क अधिनियम, 1958 के तहत दी गई है।

बिटक्वाइन ने एक बार फिर लगाई छलांग, 55000 डॉलर का आंकड़ा किया पार

नई दिल्ली। एजेंसी

दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटक्वाइन (Bitcoin) की कीमतों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। जिससे ये कयास लगाया जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी पिछले महीने बनाए अपने रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। बुधवार को बिटक्वाइन 2.8 फीसदी की बढ़ोत्तरी के साथ 55000 डॉलर का आंकड़ा पार कर गया। हांगकांग में सुबह 9 बजकर 23 मिनट पर यह 55,600 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था। बता दें कि एक महीने पहले इसका भाव करीब 60 हजार डॉलर के पास पहुंच गया था।

यू.एस. के शेयरों में मंगलवार को उछाल आने के बाद ब्लूमबर्ग गैलेक्सी क्रिप्टो इंडेक्स पिछले दो सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया। पेप्परस्टोन ग्रुप लिमिटेड के रिसर्च हेड क्रिस वेस्टन ने एक नोट में कहा कि ये आश्चर्यजनक नहीं होगा अगर इसकी कीमत पिछले महीने का आकंडा पार कर जाए। बिटकॉइन में बढ़ती संस्थागत रुचि और संभावना है कि अमेरिकी प्रोत्साहन चेक के चलते फाइनेंशियल मार्केट में सुधार से क्रिप्टोकरेंसी में बढ़ोत्तरी हो रही है। डिजिटल टोकन पिछले साल लगभग 600 प्रतिशत का उछाल देखा गया था।

कई कंपनियों ने किया निवेश

इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला समेत कई कंपनियों ने बिटक्वाइन को डिजिटल करेंसी (Digital Currency) के तौर पर मंजूरी दी तो इसके दाम हर दिन बढ़त का नया रिकॉर्ड बनाने लगे थे। इसके बाद जब इसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए तो टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क ने रोज तेजी से बढ़ती कीमतों पर सवाल उठाया। इसके बाद इसके भाव गिरने शुरू हो गए थे। अब आज इसने फिर 50 हजार डॉलर के आंकड़े को पार कर लिया है।

क्या होती है बिटकॉइन

बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी यानी आभासी मुद्रा है। जैसे दुनिया में बाकि करेंसी होती है, वेसे ही बिटक्वाइन है। बिटक्वाइन को हम केवल ऑनलाइन वॉलेट में ही रख सकते हैं। बिटक्वाइन का आविष्कार सातोशी नाकामोतो ने 2009 में किया था। इस प्रकार बिटक्वाइन एक डिसेंट्रालाइज करेंसी है. बिटक्वाइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है।

सरकार के राजकोषीय उपायों से तीसरी तिमाही में विकास दर रही सकारात्मकः वित्त मंत्री

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार की ओर से किए गए राजकोषीय उपायों से चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 0.4 फीसदी की विकास दर देखने को मिली। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020-21 में अर्थव्यवस्था आठ फीसदी संकुचित होगी। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ''सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2020-21 में किए गए राजकोषीय उपायों से अर्थव्यवस्था में सतत रूप से खर्च हो रहा है तथा अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तेजी से सुधार हुआ है।'' निर्मला ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों पर लगी पाबंदियों में ढील देने से आपूर्ति संबंधी बाधाएं कम हुई हैं तथा महंगाई दर 7.6 फीसदी से गिरकर 4.1 फीसदी हो गई है। उन्होंने कहा, ''महंगाई दर कम होने से लोगों की वास्तविक क्रय शक्ति बढ़ी है।''

Petrol Diesel under GST:

पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने से क्यों कतराते हैं राज्य

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। देश के ज्यादातर शहरों में पेट्रोल 100 के करीब तो डीजल 90 के पार है। इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल के करीब है। विपक्षी दल तंज कसते हुए कहते हैं कि सीता के देश नेपाल में पेट्रोल और डीजल की कीमते नियंत्रण में है, रावण के देश श्रीलंका में पेट्रोलियम उत्पाद नियंत्रण में हैं तो भारत में कीमतें बेलगाम क्यूं हैं। यह बात अलग है कि जो विपक्षी दल आवाज उठा रहे हैं जब वो सरकार में थे हालात उनके नियंत्रण से बाहर थी। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और उससे निपटने का तरीका क्या है।

जीएसटी के दायरे में ना लाने के लिए दो तर्क

जानकार कहते हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने से राज्य दो वजहों से परहेज करते हैं। पहली वजह तो यह है कि जीएसटी के दायरे में ज्यादातर सामानों के आने की वजह से राज्य अब सीधे सीधे टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपने बकाये के लिए केंद्र सरकार की तरफ देखना पड़ता है। बंगाल और पंजाब जैसे राज्य बार बार आरोप लगाते हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है। केंद्र सरकार जीएसटी बकाया देना है लेकिन उसमे तरह तरह के रोड़े अटकाए जा रहे हैं और उसका असर राज्य के विकास पर पड़ रहा है।

राजस्व हानि का खतरा

दूसरा पक्ष यह है कि पेट्रोलियन उत्पादों पर दो हिस्सों में टैक्स लगता है। एक तो केंद्र सरकार बेस प्राइस पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है तो दूसरी तरफ अपनी तरफ से वैट लगाती हैं और इस तरह से राज्य को उन्हें राजस्व हासिल होता है। राज्यों को डर है कि अगर पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो उन्हें राजस्व की कमी का सामना करना पड़ेगा और वो जनहित के काम नहीं कर सकेंगे। यह सबसे बड़ी वजह है कि राज्य सरकारें इन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखना चाहती हैं।

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का क्या कहना है

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में कहा था कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी सरकारों को मिलजुल कर सोचने की जरूरत है। पेट्रोलियम पदार्थों की बेलगाम कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए जीएसटी के दायरे में लाना प्रभावी कदम है लेकिन इसके लिए जीएसटी काउंसिल से अनुमोदन होना जरूरी है। हालांकि विपक्ष खासतौर से कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर गेंद राज्यों के पाले में डालकर खुद को आजाद रखना चाहती है।

50 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर पर 1 अप्रैल से ई-चालान जरूरी

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सालाना 50 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए 1 अप्रैल से बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) लेनदेन पर ई-चालान देना जरूरी होगा। जीएसटी चोरी रोकने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 1 अक्तूबर, 2020 को 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए बी2बी लेनदेन पर ई-चालान जरूरी किया था।

जीएसटी चोरी रोकने के लिए सरकार ने तीसरी बार किया बदलाव

1 जनवरी, 2021 को इसे बदलकर 100 करोड़ टर्नओवर वाले कारोबारियों पर लागू कर दिया, जिसे एक बार फिर घटाकर 50 करोड़ किया गया है। ई-इनवॉइसिंग के तहत करदाता अपने चालान को पंजीकरण पोर्टल (आईआरपी) पर ऑनलाइन दाखिल करता है। आईआरपी चालान में दी गई सूचनाओं के सत्यापन के बाद डिजिटल हस्ताक्षर, विशेष चालान संख्या और क्यूआर कोड के साथ नया ई-चालान जारी करता है। ईवाई टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा, इसका मकसद कर चोरी रोकने के साथ डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। हालांकि, इस दायरे में आने वाले कारोबारियों के पास नए नियम के अनुपालन के लिए समय काफी कम है।

मकानों की बिक्री में गिरावट 2020-21में 34% रहेगी, अगले वर्ष तेज सुधार की उम्मीद : इंडिया रेटिंग्स

नयी दिल्ली। एजेंसी

कोरोना महामारी के चलते चालू वित्त वर्ष 2020-21 में आवासीय इकाइयों की बिक्री में 34 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। हालांकि निम्न तुलनात्मक आधार के हिसाब से अप्रैल से शुरू हो रहे वर्ष 2021-22 में मांग में करीब इसी तेजी से वृद्धि भी दिख सकती है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने यह अनुमान व्यक्त किया है। एजेंसी का अनुमान है कि रियल एस्टेट क्षेत्र अगले वित्त वर्ष में अंग्रेजी 'के' आकार की वापसी कर सकता है। इसका अर्थ है कि बाजार नरमी से पूरी तरह से तो नहीं उबर सकेगा पर चालू वित्त वर्ष में गिरावट के बाद वृद्धि दर के आंकड़े अच्छे दिखेंगे। एजेंसी ने एक बयान में कहा, ''वित्त वर्ष 2021 में सालाना आधार पर 34 प्रतिशत की गिरावट के बाद वित्त वर्ष 2022 में बिक्री में 30 फीसदी की वृद्धि दर्ज की जा सकती है।'' हालांकि एजेंसी ने इस बात पर जोर दिया कि वित्त वर्ष 2022 में समग्र बिक्री अभी भी वित्त वर्ष 2019-20 के स्तर से लगभग 14 प्रतिशत कम रह सकती है। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में कुल 32.6 करोड़ वर्गफीट आवासीय क्षेत्र की बिक्री हुई थी। एजेंसी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीने में सालाना आधार पर बिक्री में 41 फीसदी की गिरावट रही है। पूरे वित्त वर्ष में यह गिरावट 34 प्रतिशत रह सकती है।

स्वच्छता के पंच हेतु

मॉडर्न ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स द्वारा थ्री-आर (3R) से शिवलिंग का निर्माण

■वेस्ट मैटेरियल के उपयोग से बनाया गया है यह 3R शिवलिंग। ■शिवरात्रि के पावन अवसर पर मॉडर्न ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स द्वारा अभिनव पहल। ■मॉडर्न कैंपस अलवासा में स्थापित किया गया है यह 3R शिवलिंग ■मॉडर्न इंटरनैशनल स्कूल के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने बनाया है यह सुंदर आकृति। ■त्योहारों एवं पूजन के माध्यम से भी दिया जा सकता है स्वच्छता का संदेश।

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मॉडर्न ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स इंदौर द्वारा स्वच्छता अभियान में योगदान हेतु एक और अभिनव प्रयोग किया गया गया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मॉडर्न इंटरनैशनल स्कूल के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा कागज़ एवं अन्य अनुपयोगी वस्तुओं के रीसायकल-रीयूज के द्वारा सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया गया। शिवलिंग के आस पास की साज सज्जा भी वेस्ट मैटेरियल के रीयूज के द्वारा ही गयी। यहाँ जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती प्रद्न्या कस्तूरे ने बताया कि पर्यावरण की सुरक्षा एवं नवाचार दोनों आवश्यक है। संस्था के समूह निदेशक डॉ. पुनीत द्विवेदी (ब्रांड एंबेसडर-स्वच्छ इंदौर) ने विद्यार्थियों को ऐसे अन्य अभिनव प्रयोगों को करने हित प्रेरित किया। इस अनूठे निर्माण के लिये समूह निदेशक डॉ पुनीत द्विवेदी द्वारा फ़ैकल्टी दिव्या लोटारकर , सपना जाट, पद्मिनी पाल एवं शैलेंद्र यादव को सराहा गया और ऐसे ही विद्यार्थियों को कला, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण से अवगत कराते रहने हेतु निर्देशित किया गया। श्री -आर शिवलिंग का पूजन कर स्वच्छता के मंत्र को जन-जन तक पहुँचाने हित मॉडर्न ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स ने संकल्प लिया। संस्था के अध्यक्ष डॉ. अनिल खरया एवं उपाध्यक्ष श्री शांतनु खरया ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को 3' शिवलिंग के लिये हार्दिक बधाई दी।

7 तरह के होते हैं आयकर विभाग के नोटिस, जानिए क्या होते हैं इनके मतलब!

नई दिल्ली। एजेंसी

ये तो सभी को पता है कि आईटीआर में कोई खामी पाए जाने पर आयकर विभाग की तरफ से नोटिस आ जाता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि ये नोटिस भी कई तरह के होते हैं। अगर आपकी आय और टैक्स में कोई अंतर दिखता है तो भी नोटिस आ सकता है। गलती से कोई चीज गलत रह गई हो तो भी नोटिस आ जाता है। आइए जानते हैं आयकर विभाग के तमाम नोटिसों के बारे में और ये भी जानते हैं कि वह किस बात के लिए आते हैं।

सेक्शन 131(1ए)

आयकर अधिनियम के एमूदह 131(1A) के तहत एक असेसिंग ऑफिसर को अधिकार है कि वह इस बात पर शक कर सके कि करदाता ने कुछ आय छुपाई है। यानी आपको ये नोटिस आने पर इस बात के सबूत देने होंगे कि आपने कोई इनकम नहीं छुपाई है।

सेक्शन 133ए

एमूदह 133A के तहत अकाउंट्स के सर्वे या स्क्रूटिनी के लिए नोटिस जारी किया जाता है।

सेक्शन 142

एमूदह 142 के तहत दिया जाने वाला नोटिस सबसे कॉमन नोटिस है, जो आयकर रिटर्न फाइल नहीं करने पर दिया जाता है। इसके तहत अकाउंट्स की स्क्रूटिनी के लिए कहा जा सकता है। आयकर रिटर्न भरने पर करदाता की तरफ से दिए गए दस्तावेजों पर कोई संदेह होने की सूरत में भी ये नोटिस आ सकता है।

सेक्शन 143(1)

एमूदह 143(1) के तहत आने वाला नोटिस तब आता है जब ये पाया जाता है कि टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए कोई गलती हुई है या फिर कोई गलत जानकारी दी गई है। ऐसी सूरत में अतिरिक्त टैक्स डिमांड की जाती है।

सेक्शन 143(2)

एमूदह 143(2) के तहत नोटिस आने का मतलब है कि असेसिंग ऑफिस की तरफ से एक नियमित मूल्यांकन जांच की जाएगी।

सेक्शन 148

एमूदह 148 का नोटिस तब आएगा, जब असेसिंग ऑफिसर को लगेगा कि आपकी कुछ आय का मूल्यांकन नहीं हुआ है, ऐसी सूरत में फिर से मूल्यांकन किया जा सकता है।

सेक्शन 156

अगर करदाता की तरफ से कोई टैक्स, ब्याज, हर्जाना आदि ड्यू रह जाता है तो उसे एमूदह 156 के तहत नोटिस जारी कर के भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है।

साबू ट्रेड, सेलम रेडी-मिक्स सेगमेंट में उतरने को तैयार

नये ब्रांड के अंतर्गत मिलेट इडली और खमण रेडी-मिक्स से शुरुआत

इंदौर/ सेलम। आधुनिक समय में नाश्ते के बिना दिन की शुरुआत की कल्पना करना मुश्किल है. इसी तरह दोपहर में भी ताजा और स्वास्थ्यप्रद स्नैक अब हर व्यक्ति की जरूरत बनता जा रहा है। यहाँ तक कि रात को भी अब भरपेट खाना खाने के बजाये कई परिवार बिना तला और कम गरिष्ठ खाना पसंद करते हैं. जहां एक तरफ नाश्ते में क्या बनाया जाए, होम मेकर्स इस समस्या से जूझ रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर नाश्ता कितनी आसानी से कम समय में बन जाये, पौष्टिक हो, तला हुआ ना हो, इस पर भी लगातार ध्यान रहता है। इन सभी आम जरूरतों को ध्यान में रखते हुए साबु ट्रेड, सेलम ने रेडी मिक्स सेगमेंट में अपने दो उत्पाद कुकरी जॉकी खमण मिक्स और कुकरी जॉकी मिलेट इडली मिक्स बाज़ार में उतारने जा रहे हैं।

इसके पहले साबु ट्रेड ने भारत भर में करीब 350 से ज्यादा परिवारों के करीब 1500 लोगों में स्वाद और गुणवत्ता का परीक्षण कर सुनिश्चित किया है कि ये उत्पाद बाज़ार में अपनी विशेष जगह बना पायेंगे।

साबु ट्रेड प्रायवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गोपाल साबु ने बताया कि हमें बाज़ार के आकार और सम्भावनाओं के कारण स्नैक इंडस्ट्री हमेशा से ही आकर्षित करती रही है, जिस पर कंपनी में पिछले कुछ वर्षों से लगातार काम हो रहा था। चूँकि इनमें लगने वाले इन्ग्रेडिएन्ट हमारे द्वारा ही तैयार किये जाते हैं, इसलिए शुद्धता, गुणवत्ता और स्वाद का भरोसा करना ग्राहकों के लिये आसान होगा।

रेडी मिक्स खाद्य उत्पादों को कुछ तैयारी की आवश्यकता होती है, जैसे कि उपयोग से पहले गर्म करना या भाप में पकाना आदि। घर से काम करने वाले उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक भोजन विकल्प की तलाश में रेडी-टू-कुक (आरटीसी) श्रेणियों में बहुत सारी गतिविधियाँ देखी जा रही हैं ।

श्री साबु ने अपनी कंपनी के ब्रांड्स के बारे में बताया कि सच्चासाबु, सच्चामोती , चक्र एगमार्क, शिवज्योति, गोपाल साबुदाना और साबुदाना पापड़ एवं अल्पाहार एगमार्क हल्दी पाउडर, भगर (मोरधन) तथा हाइ फैट शुद्ध नारियल बूर्रा जैसे उत्पादों ने अपने अपने सेग्मेंट्स में उपभोक्ताओं के बीच देश भर में मजबूती से अपनी जगह बनाई हुई है, लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं, कि कुकरी जॉकी ब्रांड को भी ग्राहकों का भरपूर स्नेह मिलेगा।

विद्युत सुरक्षा सप्ताह में ली उपकरणों के सदैव उपयोग की शपथ

शहर वृत्त के आयोजन में लाइनकर्मियों का सम्मान

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मप्रपक्षेविविकं के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर के निर्देश पर जिलों में विद्युत सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इंदौर शहर वृत्त का आयोजन कंपनी के निदेशक श्री मनोज झंवर, अधीक्षण यंत्री श्री कामेश श्रीवास्तव की मौजूदगी में पोलोग्राउंड सभागार में हुआ। इस मौके पर बिजली कर्मचारियों, अधिकारियों ने लाइनों का कार्य करते समय विद्युत सुरक्षा उपकरणों के उपयोग की शपथ भी ली।

श्री मनोज झंवर ने कहा कि विद्युत सेवा आवश्यक सेवा है, इसे निर्विघ्न, निरंतर एवं सुचारू बनाए रखने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन एवं उपकरणों का उपयोग बहुत जरूरी है। आयोजन के दौरान शहर वृत्त के 10 लाइन कर्मियों का सम्मान सुरक्षा उपकरण गम बूट, हैंड ग्लोब्ज, सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, फाइबर डिस्चार्ज राड, प्लायर एवं स्क्रू ड्राइवर, टार्च आदि भेंटकर किया गया। आयोजन में प्रमुख रूप से कार्यपालन यंत्री सर्वश्री बीडी फ्रैंकलीन, मानेंद्र गर्ग, राजेश हरोड़े, गजेंद्र कुमार, शैलेंद्र भदौरिया आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे। संचालन श्रीमती सोनाली निरगुड़े ने किया।

सभी जिलों में आयोजन- मुख्य महाप्रबंधक श्री संतोष टैगोर ने बताया कि प्रबंध निदेशक श्री तोमर के निर्देश पर सभी 15 जिलों में सुरक्षा विषयक आयोजन हो रहे है। इन आयोजनों में 150 लाइन कर्मियों का सम्मान भी सुरक्षा उपकरण भेंटकर किया जा रहा है।

सेंसेक्स 254 अंकों बढ़त के साथ बंद

दवा, IT कंपनियों के शेयर चमके

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

शेयर बाजारों में लगातार तीसरे दिन तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स बुधवार को 254 अंक से अधिक की बढ़त के साथ 51,279.51 अंक पर बंद हुआ। सकारात्मक रुख के बीच दवा, आईटी और वाहन कंपनियों के शेयरों में तेजी से बाजार में मजबूती आयी। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 254.03 अंक यानी 0.50 प्रतिशत की बढ़त के साथ 51,279.51 अंक पर बंद हुआ।

इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 76.40 अंक यानी 0.51 प्रतिशत मजबूत होकर 15,174.80 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में सर्वाधिक लाभ में बजाज फाइनेंस रही। इसमें करीब 2 प्रतिशत की तेजी आयी। इसके अलावा सन फार्मा, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो और इन्फोसिस में भी बढ़त रही।

इन शेयरों में रही गिरावट

दूसरी तरफ, जिन शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, उनमें ओएनजीसी, कोटक बैंक, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक और पावरग्रिड शामिल हैं। रिलायंस सिक्योरिटीज के रणनीतिक प्रमुख विनोद मोदी ने कहा कि मुख्य रूप से सकारात्मक वैश्विक संकेतों से घरेलू बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी रही। आईटी, धातु और औषधि कंपनियों के शेयरों में एक प्रतिशत से अधिक की तेजी आई। वाहन कंपनियों के शेयरों में भी मजबूत लिवाली देखी गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर ज्यादातर खंडों के शेयर सूचकांक लाभ में रहे।

ब्रेंट क्रूड की कीमत गिरी

एशिया में शंघाई बाजार का कंपोजिट इंडेक्स और दक्षिण कोरिया का कोस्पी नुकसान में रहे जबकि हांगकांग और तोक्यो शेयर बाजार में तेजी रही। भारतीय समयानुसार दोपहर बाद खुले यूरोप के प्रमुख बाजारों में तेजी का रुझान था। इस बीच, वैश्विक कच्चा तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 0.59 प्रतिशत की गिरावट के साथ 67.12 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा था।

रिलायंस अपने कर्मचारियों, उनके परिवार के कोविड-19 टीकाकरण का बोझ वहन करेगी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने करीब 12.2 लाख कर्मचारियों और उनके करीबी पारिवारिक सदस्यों के कोविड- 19 टीकाकरण का खर्च खुद उठायेगी। इसके साथ ही रिलायंस भी उन कंपनियों के समूह में आ गई है जिन्होंने अपने कर्मचारियों को कोविड- 19 महामारी से बचाने के लिये टीका लगाने का खर्च स्वयं उठाने का फैसला किया है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसिज (टीसीएस), इन्फोसिस, एसेंचर और सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने कर्मचारियों और उनके पारिवारिक सदस्यों को टीका लगाने की लागत स्वयं वहन करने की घोषणा की है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और रिलायंस इंडस्ट्रीज की गैर- कार्यकारी निदेशक नीता अंबानी ने कर्मचारियों को भेजे एक आंतरिक संदेश में कहा है, "जैसा कि हमने पहले प्रतिबद्धता जताई थी रिलायंस आपके, आपकी पत्नी, आपके माता- पिता और टीका लगाने योग्य आपके बच्चों के टीकाकरण की पूरी लागत वहन करेगी। आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा और बेहतरी हमारी जिम्मेदारी है।" कंपनी ने अपने कर्मचारियों के टीकाकरण के लिये खास अस्पतालों के साथ गठबंधन किया है। कर्मचारियों को ये टीके वह जहां भी काम कर रहे हैं उन्हीं स्थानों में स्थित अस्पतालों में लगाये जायेंगे। रिलायंस के टीकाकरण कार्यक्रम में समूह की सभी अनुषंगियों के कर्मचारी शामिल होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के तेल और रसायन कारोबार, खुदरा उपक्रम और दूरसंचार उद्यम जियो तथा उनसे जुड़ी सहयोगी कंपनियों के कर्मचारियों और उनके प्रजीकृत आश्रितों को कंपनी टीका लगवायेगी। नीता अंबानी ने समूह में आंतरिक तौर पर भेजे गये संदेश में कहा है, "मुकेश और मेरे लिये प्रियजनों की खुशियों और बेहतर स्वास्थ्य काफी मायने रखता है और यह हमारे लिये एक परिवार का हिस्सा है - रिलायंस परिवार।" उन्होंने उन सभी कर्मचारियों से आग्रह किया है जो कि सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीका लगने के पात्र है, वह जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करा लें।

अमेज़न इंडिया के ऑपरेशंस में तेजी लाते हुए इंदौर की ये आईएचएस पार्टनर अपनी उद्यमशीलता की विरासत का निर्माण कर रही हैं

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

जीवन में कठिन समय आने पर, कुछ महिलाएं आगे बढ़कर स्थिति को संभालती हैं और इसे बदलने का काम करती हैं। ये महिलाएं हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना पसंद करती हैं और अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगी दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन जाती हैं। ऐसी ही कुछ महिलाओं में इंदौर की सुनीता डाबी भी शामिल हैं।

सुनीता कुछ समय से अपने परिवार की जरूरतों की देखभाल कर रही हैं। कुछ वर्षों पहले अपने पति से अलग होने के बाद, उनके बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। सुरक्षा गार्ड की नौकरी से होने वाली आमदनी बहुत कम थी और अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करना और दो बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करना एक चुनौती बन रही थी। लेकिन वह बच्चों को उज्जवल भविष्य देने के अपने संकल्प को लेकर मजबूती से खड़ी थीं और अपने पिता की दुकान, भैरू भाई किराना स्टोर में उनकी मदद करने लगीं। उसकी अदम्य भावना ने उसे अन्य रास्तों की तलाश करने में मदद की, जिसने उन्हें अतिरिक्त कमाई करने में सक्षम बनाया। इसी समय, उन्हें अमेज़न के आई हैव स्पेस (आईएचएस) प्रोग्राम के बारे में पता चला और इससे अपने पिता के व्यवसाय को बढ़ाने की संभावनाओं के बारे में उनकी समझ बनी। उन्होंने तुरंत प्रोग्राम में दाखिला लिया और यहीं से उनकी उद्यमशीलता की यात्रा शुरू हो गयी।

आईएचएस प्रोग्राम एक अद्वितीय पहल है जो स्थानीय स्टोर मालिकों को अमेज़न के साथ साझेदारी करने में सक्षम बनाता है और उनकी नियमित आय में अतिरिक्त कमाई जोड़ता है, और इसके साथ ही, उनकी स्थानीय दुकानों के लिए ग्राहकों की संख्या में भी वृद्धि करता है। कई अन्य स्टोर मालिकों की तरह, सुनीता भी अपने स्टोर के 2-4 किलोमीटर के दायरे में ग्राहकों को पिकअप और डिलीवरी सेवाएं प्रदान करती हैं।

अमेज़न के साथ 3 साल से अधिक समय तक आईएचएस पार्टनर के रूप में काम करते हुए, सुनीता स्टोर की देखभाल करते हुए और अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं को आसानी से निभाते हुए, एक स्थिर कमाई करने में सक्षम हो चुकी हैं। प्रोग्राम से हुई अतिरिक्त आय ने सुनीता को काफी हद तक अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने और अपने बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करने में सक्षम बनाया है, जिसके वे हकदार भी हैं। सुनीता की कार्यशैली अमेज़न के लीडरशिप सिद्धांतों की मिसाल पेश करती है और वह जो काम करती हैं, उसमें समाधान को ध्यान में रखते हुए और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए, काम करने के लिए जानी जाती हैं। सुनीता कई भूमिकाएं निभाती हैं और उनमें अधिक से अधिक काम करने की लगन है। वह अपने दिन की शुरुआत डिलिवरी देने से करती हैं और फिर पूरे दिन किराना स्टोर की देखभाल करती हैं।

अपने अनुभव के बारे में बताते हुए, सुनीता कहती हैं कि 'अमेज़न से मुझे जो सहयोग और स्वतंत्रता मिली है, उसने मुझे अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने और अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया है। सबसे बड़ी जीत वह सम्मान और मान्यता है जो मुझे समाज में मिलती है और जब दूसरे लोग मुझे एक मददगार के रूप में देखते हैं। इससे मुझे काम करते रहने के लिए आत्मविश्वास और प्रेरणा मिलती है। अमेज़न के साथ आईएचएस पार्टनर बनना मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ रहा है।'

UPI QR कोड में GST कंपोनेंट फीचर!

पेमेंट करने वालों को कैसे होगा फायदा; जानें सरकार का प्लान

नई दिल्ली। एजेंसी

NPCI UPI QR कोड में उएऊ कंपोनेंट शामिल करने पर काम कर रही है। रोज एक अरब UPI ट्रांजेक्शन संभालने की क्षमता विकसित करने के लिए एनपीसीआई, बैंकों और पेमेंट कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है।

हो सकता है कि जल्द ही आप UPI (Unified Payment Interface) के जरिए सरकार को जीएसटी (Goods and Services Tax) का भुगतान करें। सरकार UPI QR कोड में जीएसटी कंपोनेंट शामिल करने और इसके अलग से दिखना सक्षम बनाने पर विचार कर रही है। UPI QR कोड में जीएसटी कंपोनेंट ऐड होने से सरकार जीएसटी के डिजिटली भुगतान पर इंसेंटिव दे सकेगी।

क्या कहना है NPCI का

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के सीईओ दिलीप आस्बे का कहना है कि एनपीसीआई UPI QR कोड में जीएसटी कंपोनेंट शामिल करने पर काम कर रही है। रोज एक अरब यूपीआई ट्रांजेक्शन संभालने की क्षमता विकसित करने के लिए एनपीसीआई, बैंकों और पेमेंट कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। नौ माह में यूपीआई ने 250 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की है।

जुड़ चुकी है Paytm भी

आस्बे पेटीएम (Paytm) द्वारा अपने साउंडबॉक्स के अपग्रेडेड वर्जन की लॉन्चिंग के लिए आयोजित किए गए ईवेंट में बोल रहे थे। पेटीएम साउंडबॉक्स वह डिवाइस है जो पेमेंट हो जाने की पुष्टि ऑडियो व स्क्रीन के जरिए उपलब्ध कराती है। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने ईवेंट में कहा कि पेटीएम ने जीएसटी कंपोनेंट फीचर वाले ळ्ह्ँ कोड को विकसित करने के लिए काम शुरू कर दिया है।

फरवरी में कितना रहा था GST कलेक्शन

माल एवं सेवा कर (उएऊ) का कलेक्शन फरवरी में लगातार पांचवें महीने एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि फरवरी में जीएसटी कलेक्शन सात प्रतिशत बढ़कर 1.13 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत है। हालांकि, फरवरी के जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा जनवरी से कम रहा है। जनवरी में जीएसटी कलेक्शन 1,19,875 करोड़ रुपये रहा था।

महिलाओं के लिये पेश किया सोशल मीडिया मंच 'हर सर्किल'

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता मुकेश अंबानी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से रविवार को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'हर सर्किल' पेश किया। उन्होंने एक बयान में कहा कि 'हर सर्किल' को महिलाओं से जुड़ी सामग्रियों के लिये विशेष रूप से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह अपनी तरह का पहला डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण और वैश्विक स्तर पर महिलाओं के उत्थान के लिये काम करना है। सहभागिता, नेटवर्किंग और आपसी सहयोग के लिये 'हर सर्किल' प्लेटफॉर्म महिलाओं को एक सुरक्षित माध्यम प्रदान करेगा।

नीता अंबानी ने कहा, 'जब महिलाएं महिलाओं का ध्यान रखती हैं, तो अविश्वसनीय चीजें होती हैं। मैं अपने जीवन भर मजबूत महिलाओं से घिरी रही, जिनसे मैंने करुणा, लचीलापन और सकारात्मकता सीखी; और बदले में वही सीख मैंने दूसरों को देने का प्रयास किया। मैं 11 लड़कियों के परिवार में पली-बढ़ी, जहां मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया गया।'' उन्होंने कहा, 'मुझे खुशी है कि हम हर सर्किल डॉट इन के माध्यम से लाखों महिलाओं के लिये समर्थन और एकजुटता का एक विस्तृत सर्किल बना सकते हैं, जिसमें हर महिला का स्वागत होगा। 24x7 वैश्विक नेटवर्किंग, डिजिटल क्रांति और सबके सहयोग से 'हर सर्किल' सभी संस्कृतियों, समुदायों और देशों की महिलाओं के विचारों तथा पहलों का स्वागत करेगा। समानता और सिस्टरहुड इसकी विशेषता होगी।'' हर सर्किल, डेस्कटॉप और मोबाइल पर खुलने वाली वेबसाइट है। यह गूगल प्ले स्टोर और माई जियो ऐप स्टोर पर मुफ्त उपलब्ध है। हर सर्किल में यूजर्स फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी यह वेबसाइट अंग्रेजी में उपलब्ध है। बाद में अन्य भारतीय भाषाओं में इसे पेश किया जायेगा।

रसायन क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना लाने पर विचार कर रही है सरकार

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार रसायन क्षेत्र के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लाने पर विचार कर रही है। इससे घरेलू विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। रसायन एवं उर्वरक मंत्री डी वी सदानंगद गौड़ा ने शुक्रवार को 'बजट घोषणाओं-2021-22 के क्रियान्वयन की रणनीति' पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार देश के रसायन एवं पेट्रो रसायन क्षेत्र के लिए नीतियां बनाने को बातचीत का रुख अपना रही है। वेबिनार का आयोजन फिक्की के रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने किया था। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन अकेले सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता। ''हमें उद्योग को भरोसे में लेना होगा, जिससे अप्रैल के पहले सप्ताह से क्रियान्वयन शुरू हो सके।''

अमेरिका से 300 करोड़ डॉलर में 30 सशस्त्र ड्रोन्स खरीदने की तैयारी में भारत

नई दिल्ली। एजेंसी

पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान से लगातार बिगड़ते संबंधों के बीच भारत ने खुद की ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया है। पहले नए हथियारों की खरीद के साथ आधुनिक मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा था और अब सरकार ने सीमा पर चौकसी और सुरक्षा बढ़ाने के लिए अमेरिका से 30 सशस्त्र ड्रोन खरीदने की योजना बनाई है। इस खरीद को अगले महीने के अंत तक आधिकारिक मंजूरी मिलने की संभावना है। इससे भारत की ताकत में बड़ा इजाफा होगा।

300 करोड़ डॉलर की लागत से खरीदे जाएंगे ड्रोन्स

जानकारी के अनुसार मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि भारत अगले महीने 300 करोड़ डॉलर की इस डील को मंजूरी दे सकता है। इस डील के तहत 30 ईं-ॅ प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन खरीदे जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन सशस्त्र ड्रोन्स का निर्माण सेन डिएगो स्थित जनरल एटॉमिक्स द्वारा किया जाएगा। इन सशस्त्र ड्रोन्स के भारतीय सेना में शामिल होने के बाद सुरक्षा स्तर पर सेना की ताकत में बढ़ोतरी होगी। अब तक निगरानी के लिए ही किया जा रहा था ड्रोन्स का इस्तेमाल अब तक भारतीय सीमाओं पर ड्रोन्स का इस्तेमाल निगरानी और गतिविधियों की जानकारी जुटाने के लिए ही किया जाता रहा है। इसके लिए भारत ने कुछ समय पहले ही अमेरिका से दो ड्रोन लीज पर लिए थे और अब खरीद की योजना बनाई है।

क्या है MQ-9B ड्रोन की खासियत?

MQ-9B ड्रोन लगातार 48 घंटों तक उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं यह अपने साथ एक बार में 1700 किलोग्राम तक का वजन भी लेकर काम कर सकता है। इसके अलावा इनके जरिए आवश्यकता पड़ने पर फायरिंग भी की जा सकती है। भारतीय सेना में इनके शामिल होने के बाद भारतीय सेना दक्षिण भारतीय महासागर में चीनी युद्धपोतों पर बेहतर तरीके से निगरानी कर सकेगी। इसके अलावा हिमालय में भारत-पाकिस्तान सीमा के विवादित क्षेत्र में भी मदद मिलेगी।

अमेरिका के रणनीतिक सुरक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा है भारत

बता दें कि भारत वर्तमान में अमेरिका के रणनीतिक सुरक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा है। खासतौर से चीन को लेकर ये साझेदारी और मजबूत हुई है। हालांकि, इस डील को लेकर अभी किसी तरह कि आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारतीय रक्षा मंत्रालय और जनरल एटॉमिक्स के प्रवक्ताओं ने मामले पर अभी कुछ नहीं कहा है। वहीं, पेंटागन अधिकारियों की तरफ से डील को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है।

12 मार्च को होगी पहली क्वाड बैठक

स्थानीय मीडिया के अनुसार अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के इस महीने भारत का दौरा करने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं, राष्ट्रपति जो बाइडन जल्द ही क्वाड बैठक के जरिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समकक्षों के साथ बैठक करेंगे। भारत सरकार की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार यह मुलाकात 12 मार्च को वर्चुअल तरीके से होने जा रही है। इसमें आपूर्ति श्रृंखला, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन आदि मुद्दों पर चर्चा होगी।

गुरुवार को शिव और सिद्ध योग में शिवरात्रि, इस दिन शिवपूजा से मिलेगा अभीष्ट फल

फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। यदि शिवरात्रि त्रिस्पृशा अर्थात त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या के स्पर्श से युक्त हो, तो परमोत्तम मानी गई है। गुरुवार 11 तारीख को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रातःकाल त्रयोदशी और दोपहर 2.39 के पश्चात चतुर्दशी तिथि है। गुरुवार को यदि शिवरात्रि पड़े तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे एश्वर्य योग भी कहा जाता है। इस दिन शिव और सिद्ध योग है तथा श्रीवत्स और सौम्य योग भी है, जो कि अत्यंत शुभ है। यह पर्व सत्य और शक्ति दोनों को पोषित करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि में चन्द्रमा सूर्य के समीप होता है। अतः इसी समय जीवन रूपी चन्द्रमा का शिवरूपी सूर्य के साथ योग होता है। अतः इस चतुर्दशी को शिवपूजा अभीष्ट फल देने वाली होगी। शिव पुराण की ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। उनका वर्णन कुछ इस प्रकार मिलता है: फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम आदिदेवो महानिशि। शिवलिंगतयोद्भूतः कोटिसूर्य समप्रभः? इस दिन भद्रा रहेगी, लेकिन शिवपूजन में भद्रा निष्प्रभावी होती है। सर्वकामना पूर्ति के लिए नदी के तट से लाई गई मिट्टी से बने शिवलिंग की विधि-विधान से पूजा करें। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की अष्ट मूर्तियों को आठ मन्त्रों से पुष्पांजलि दें। घर के वास्तु दोषों का शमन होगा। अपने घर के पूर्व क्षेत्र से प्रारम्भ कर सभी आठ दिशाओं में मंत्र का उच्चारण करते हुए पुष्प और जल अर्पित करें। मंत्र इस प्रकार हैं: ऊं शर्वाय क्षितिमूर्तये नमः। ऊं भवाय जलमूर्तये नमः। ऊं रुद्राय अग्निमूर्तये नमः। ऊं उग्राय वायुमूर्तये नमः। ऊं भीमाय आकाश मूर्तये नमः। ऊं पशुपतये यजमानमूर्तये नमः। ऊं महादेवाय सोममूर्तये नमः। ऊं ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः।

शिवरात्रि के दिन किस कामना के लिए कौन से शिवलिंग पूजें

शव से शिव होने की यात्रा ही जड़ से चैतन्य होने की यात्रा है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को मनाया जाने वाला यह पर्व 'शिवरात्रि' के नाम से जाना जाता है। इस दिन भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। इस दिन शिव मंत्र जप-हवन-अभिषेक हवन का बड़ा महत्व है। यदि मंदिर में पूजन इत्यादि करें तो ठीक अन्यथा घर पर भी पूजन कार्य किया जा सकता है। पूजा के लिए आवश्यक है शिवलिंग। नंदी को एक बड़े पात्र में रखें। शिव जी की जलाधारी का मुंह उत्तर दिशा की ओर रखते हुए पूजन प्रारंभ किया जा सकता है। शिवलिंग कई प्रकार के उपयोग में लाए जाते हैं हर शिवलिंग का फल अलग-अलग है।

1. पार्थिव शिवलिंग- हर कार्य सिद्धि के लिए।
2. गुड़ के शिवलिंग- प्रेम पाने के लिए।
3. भस्म से बने शिवलिंग- सर्वसुख की प्राप्ति के लिए।
4. जौ या चावल या आटे के शिवलिंग- दाम्पत्य सुख, संतान प्राप्ति के लिए।
5. दही से बने शिवलिंग- ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए।
6. पीतल, कांसी के शिवलिंग- मोक्ष प्राप्ति के लिए।
7. सीसा इत्यादि के शिवलिंग- शत्रु संहार के लिए।
8. पारे के शिवलिंग- अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के लिए।

घर की छत पर ध्वजा लगाने से कटेंगे रोग-दोष, होंगे चमत्कार

भारत की सनातन संस्कृति की धरोहर का सांस्कृतिक दूत है। आदि काल से वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, आर्य संस्कृति, भारतीय संस्कृति एक दूसरे के पर्याय हैं जिसमें समस्त मांगलिक कार्यों के प्रारंभ करते समय उत्सवों में, पर्वों में, घरों-मंदिरों-देवालयों-वृक्षों, रथों-वाहनों पर भगवा ध्वज या केसरिया पताकाएं फहराई जाती रही हैं। हालांकि ज्योतिष के अनुसार ध्वज लगाने के कारण और उनके लाभ अलग-अलग हैं। इसके अलावा हर घर में कोई ना कोई वास्तु दोष होते ही हैं, जिससे सकारात्मक उर्जा प्रभावित होती है। इससे परिवार के सदस्यों को आए दिन कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दोष को दूर करने में घर की छत पर लगा झंडा यानि ध्वज बड़ा लाभदायक और शुभ माना जाता है। मान्यता है कि किसी भी भवन की छत रहने वाले लोगों की कुंडली का बारहवां भाव यानि घर होती है। इसलिए ग्रहों से संबंधित दोष को शांत करने के लिए हनुमान जी या दुर्गा माता की पताका लगाई जाती है। ज्यादातर लोग नवरात्रि के दौरान इन ध्वज-

पताकाओं को अपने घर, भवन पर लगाते हैं। वास्तु नियम अनुसार अग्नि कोण यानि दक्षिण पूर्व कोने में ध्वज लगाना उचित माना गया है। इस तरफ झंडा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है व घर में बरकत रहती है और सकारात्मक उर्जा का संचार होता है।

वास्तु अनुसार घर के उत्तर-पश्चिम कोने में झंडा लगाना भी विशेष फलदायक माना जाता है। इस तरह वास्तु अनुसार दिशा में झंडा लगाने से घर में धन की वृद्धि व तरक्की होती है और लाल,केसरिया,भगवा या नारंगी का झंडा लगाया जा सकता है। इन झंडों पर देवी मां व हनुमान जी या शुभ चिन्ह प्रतीक अंकित होना चाहिए जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इस तरह घर की छत पर ध्वज-पताका लगाकर सकारात्मक उर्जा व शुभ फलों की प्राप्ति की जा सकती है।

अलग-अलग होते हैं ध्वज और पताका

ध्वज और पताका अलग-अलग होते हैं दोनों को ही हम झंडा मान सकते हैं। पताका त्रिकोणाकार होती है जबकि ध्वजा चतुष्कोणीय। प्रत्येक हिन्दू देवी-देवता अपने साथ अस्त्र-शस्त्र तो रखते ही हैं साथ ही उनका एक ध्वज भी होता है। यह ध्वज उनकी पहचान का प्रतीक माना गया है। भारतीय संस्कृति में समस्त मांगलिक कार्यों के प्रारंभ करते समय उत्सवों में, पर्वों में, घरों-मंदिरों-देवालयों-वृक्षों पर भगवा ध्वज या केसरिया पताकाएं फहराई जाती रही हैं।

कैसा होना चाहिए ध्वज

स्वास्तिक या ॐ लगा हुआ केसरिया ध्वज होना चाहिए। दो प्रकार का ध्वज होता है। एक त्रिभुजाकार और दूसरा दो त्रिभुजाकार ध्वज। दोनों में से कोई एक प्रकार का ध्वज लगा सकते हैं। भगवा ध्वज में तीन तत्व-ध्वजा, पताका (डोरी) और डंडा-जिन्हें ईश्वरीय स्वरूप माना गया है जो आधिभौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक हैं। यह ध्वजा परम पुरुषार्थ को प्राप्त कराती है एवं सभी प्रकार से रक्षा करती है।

क्यों लगाते हैं ध्वज

●ध्वजा को विजय और सकारात्मकता ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए पहले के जमाने में जब युद्ध में या किसी अन्य कार्य में विजय प्राप्त होती थी तो ध्वजा फहराई जाती थी। इससे यश, कीर्ति और विजय मिलती है। ध्वजा या झंडा लगाने से घर में रहने वाले सदस्यों के रोग, शोक व दोष का नाश होता है और घर की सुख व समृद्धि बढ़ती है। ●वास्तु के अनुसार भी ध्वजा को शुभता का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि घर पर ध्वजा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश तो होता ही है साथ ही घर को बुरी नजर भी नहीं लगती है।●ज्योतिष के अनुसार राहु को रोग, शोक व दोष का कारक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि घर के उत्तर पश्चिम में ध्वजा लगाने से घर में रहने वाले सदस्यों के रोग, शोक व दोष का नाश होता है और घर की सुख व समृद्धि बढ़ती है। ●घर की छत पर लगाने वाले ध्वज रणभूमि में रथ पर लगाने वाले ध्वज दोनों में कुछ फर्क होता है। रणभूमि में अवसर के अनुकूल 8 प्रकार के झंडों का प्रयोग होता था। ये झंडे थे- जय, विजय, भीम, चपल, वैजयन्तिक, दीर्घ, विशाल और लोल। ये सभी झंडे संकेत के सहारे सूचना देने वाले होते थे। लोल झंडा भयंकर मार-काट का सूचक था।●घर की छत पर तीन रंग में से किसी एक रंग का ध्वज लगा सकते हैं। गेरू और भगवा रंग एक ही है, लेकिन केसरिया में मामूली-सा अंतर है। इसके अलावा तीसरा रंग है पीला। ●घर के ऊपर वायव्य कोण में स्वास्तिक या ॐ लगा हुआ केसरिया ध्वज लगाकर रखें। इससे यश, कीर्ति और विजय मिलती है।

समस्त व्रतों का पुण्य प्रदान करता है इस दिन रखा गया उपवास

फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आने वाली शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस पावन दिन वास्तु शास्त्र से जुड़े कुछ उपाय करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विपत्तियां दूर हो जाती हैं। इस पावन दिन शिवलिंग पर भगवान शिव को प्रिय चीजें अर्पित करें। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का जलाभिषेक करें। थोड़ा जल घर लाकर ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पूरे घर में छिड़कें। इससे घर में मौजदू वास्तुदोष दूर हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के शुभ दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर मंदिर जाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की एकसाथ पूजा करें। माता पार्वती को शृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। शाम के समय घी का दीपक जलाकर भगवान शिव का ध्यान करें। जो व्यक्ति वर्षभर कोई व्रत उपवास नहीं रखता है और वह महाशिवरात्रि का व्रत रखता है तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि पर जरूरतमंदों को भोजन कराने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस त्योहार पर नंदी को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख-समृद्धि आती है। महाशिवरात्रि के दिन घर के मुख्य द्वार और सभी खिड़कियां खुली रखें। साथ ही मुख्य द्वार पर लाल सिंदूर से स्वास्तिक का निशान बनाएं और दोनों ओर शुभ लाभ लिखें। इस दिन कालसर्पयोग से मुक्ति के लिए भी विशेष उपाय किए जाते हैं। इस दिन नाग-नागिन के जोड़े को शिवलिंग पर अर्पित करने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इस व्रत में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। अगर किसी तरह की शारीरिक परेशानी है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।

2020-21 में आम उत्पादन में 4.24 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद : कृषि मंत्रालय

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश में आम का उत्पादन जून में समाप्त होने वाले फसल वर्ष 2020-21 में 4.24 प्रतिशत बढ़कर दो करोड़ 11.2 लाख टन होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। 'फलों के राजा', आम का उत्पादन, फसल वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) के दौरान दो करोड़ 2.6 लाख टन का हुआ था। दक्षिणी और पश्चिमी भारत से आम का आगमन शुरू हो गया है, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में आम का मौसम जून के मध्य से शुरू होगा। फसल वर्ष 2020-21 के लिए मंत्रालय द्वारा जारी बागवानी फसल उत्पादन के पहले अनुमान के अनुसार हालांकि, खरबूजा और तरबूज जैसे अन्य ग्रीष्मकालीन फलों का उत्पादन, पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा कम रहने का अनुमान है।

इस साल खरबूजे का उत्पादन 13 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 13.6 लाख टन का उत्पादन हुआ था। तरबूज का उत्पादन पिछले साल के 31.5 लाख टन के मुकाबले 31.2 लाख टन रहने का अनुमान है। केले का उत्पादन भी फसल वर्ष 2020-21 में बढ़कर तीन करोड़ 37.5 लाख टन होने का अनुमान है जो पिछले साल तीन करोड़ 25.9 लाख टन का हुआ था। मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल देश में कुल फलों का उत्पादन बढ़कर 10 करोड़ 32.2 लाख टन होने की संभावना है, जो पिछले साल 10.2 करोड़ टन ही था।

प्रमुख सब्जियों में - आलू और प्याज का उत्पादन - पिछले वर्ष से कहीं अधिक होने का अनुमान है। टमाटर के मामले में, उत्पादन पिछले साल के दो करोड़ 11.7 लाख टन से घटकर इस साल दो करोड़ 1.4 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है। प्याज का उत्पादन पिछले साल के दो करोड़ 60.9 लाख टन से बढ़कर इस साल दो करोड़ 62.9 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि आलू का उत्पादन पिछले साल के चार करोड़ 85.6 लाख टन से बढ़कर पांच करोड़ 31.1 लाख टन होने की संभावना है। देश में कुल सब्जियों का उत्पादन वर्ष 2020-21 में बढ़कर 19 करोड़ 36 लाख टन होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष 18 करोड़ 89 लाख टन रहा था।

इस साल शहद का उत्पादन 1,20,000 टन होने पर पूर्ववत रहने का अनुमान है, जबकि इस साल मसाला उत्पादन मामूली कम यानी एक करोड़ 2.4 लाख टन रहने का अनुमान है। आंकड़ों में कहा गया है कि बागवानी फसलों का कुल उत्पादन फसल वर्ष 2020-21 में बढ़कर 32 करोड़ 65.7 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले साल 32 करोड़ 7.6 लाख टन का हुआ था।

5जी के लिए ज्यादा इंतजार नहीं, तीन महीने में लग सकता है नेटवर्क

नई दिल्ली। एजेंसी

दूरसंचार उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में 5जी नेटवर्क तीन महीने में लगाया जा सकता है। लेकिन, यह सीमित क्षेत्रों में ही होगा। उनके मुताबिक इस तकनीक को समर्थन के लिए ऑप्टिकल फाइबर आधारित ढांचा अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसलिए इस क्षेत्र में अभी और काम करने की जरूरत है।

5जी सेवाओं के नेटवर्क पर निर्णय लेना होगा

नोकिया इंडिया में मार्केटिंग और कॉरपोरेट अफेयर्स के प्रमुख अमित मारवाह का कहना है कि भारत को 5जी सेवाओं के नेटवर्क पर ठोस निर्णय लेना होगा। अन्यथा, वह अगली पीढ़ी की तकनीक का लाभ लेने से चूक जाएगा। मारवाह ने कहा, ''यदि हम जल्द 5जी शुरू नहीं करते हैं, तो संभवतः चूक जाएंगे। 5जी ऑपरेटरों के लिए पैसा बनाने को बिक्री चैनल नहीं है। यह देश और दुनिया में नए आर्थिक मूल्य के सृजन के लिए समय की जरूरत है।''

देशी उपकरणों का हो इस्तेमाल

दूरसंचार निर्यात संवर्द्धन परिषद के चेयरमैन संदीप अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि 5जी में स्थानीय स्तर पर विनिर्मित उपकरणों का इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा उद्देश्य से इसका नियंत्रण भारत के पास होना चाहिए।

खुद नहीं बना सकते पूरी तकनीक

दूरसंचार क्षेत्र कौशल परिषद के अरविंद बाली ने कहा कि देश समूची तकनीक खुद नहीं बना सकता। उसे दूसरों का समर्थन लेने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना भारत को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन की दृष्टि से सही दिशा में एक कदम है।

पुरानी कार को कबाड़ करें, नई खरीद पर 5% छूट पाएं, सरकार का ऐलान

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पुराने वाहनों को कबाड़ करने में रूचि रखने वाले ग्राहकों के लिए एक खुशखबरी है। अब वे ऐसा करने पर नए वाहनों की खरीद पर करीब पांच प्रतिशत तक की छूट पा सकते हैं। गडकरी ने कहा, ''पुराने वाहनों को कबाड़ करने के एवज में वाहन कंपनियां ग्राहकों को नए वाहन की खरीद पर करीब पांच प्रतिशत की छूट देंगी।'' वाहनों को स्वेच्छा से कबाड़ करने की नीति की घोषणा 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई है। गडकरी ने कहा, ''इस नीति के चार प्रमुख घटक हैं। छूट के अलावा, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स और अन्य शुल्क के प्रावधान हैं। उन्हें स्वचालित सुविधाओं में अनिवार्य फिटनेस और प्रदूषण परीक्षणों से गुजरना होगा। इसके लिये देश में स्वचालित फिटनेस सेंटर की आवश्यकता होगी और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं।''

स्वचालित परीक्षण पास न कर पाने वाली गाड़ी चलाने पर लगेगा जुर्माना

उन्होंने कहा कि स्वचालित फिटनेस परीक्षण सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत किए जाएंगे, जबकि सरकार निजी भागीदारों और राज्य सरकारों को वाहनों को कबाड़ करने वाले संयंत्र लगाने में सहायता करेगी। मंत्री ने कहा कि जो वाहन स्वचालित परीक्षण पास नहीं कर पाएंगे, उन्हें चलाने पर दंड लगेगा। उन्होंने कहा कि यह नीति वाहन क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होने जा रही है। यह वाहन उद्योग को सबसे अधिक लाभकारी क्षेत्रों में से एक बना रही है, जिससे बहुत से रोजगार पैदा होंगे।

रद्दी कागज की कीमतें दोगुनी होने से कागज, गत्ता उद्योग के समक्ष संकटः आईएआरपीएमए

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश में कागज और गत्ते के उत्पादन में 65 से 70 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी रखने वाले रद्दी कागज पर आधारित उद्योग इन दिनों अप्रत्याशित संकट का सामना कर रहा है।

इनके प्रमुख कच्चे माल यानी रद्दी कागज की कीमतें पिछले छह

महीने में दोगुनी हो गई हैं। इंडियन एग्रो एंड रिसाइकिल्ड पेपर मिल्स एसोसिएशन (आईएआरपीएमए) ने एक विज्ञप्ति यह बात कही है। वाणिज्य मंत्रालय को लिखे पत्र में आईएआरपीएमए ने कहा कि देश में सालाना 2.5 करोड़ टन कागज का उत्पादन होता है। इसमें से करीब 1.7 करोड़ टन कागज का उत्पादन रद्दी कागज आधारित पेपर मिलें करती हैं। रद्दी कागज की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण कागज उत्पादन में किसी भी तरह की कमी से लिखने, छपाई करने, अखबारी कागज और पैकेजिंग इंडस्ट्री पर दुष्प्रभाव पड़ेगा।कोरोना से पहले 10 से 13 रुपये प्रति किलो वाले रद्दी कागज की कीमतें 22 से 24 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई हैं, जिससे उद्योग पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। क्राफ्ट वेस्ट पेपर की कीमतें भी 22 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई हैं, जो कोरोना से पहले की अवधि में 10 रुपये प्रति किलो के स्तर पर थीं।आईएआरपीएमए ने सरकार से हस्तक्षेप करने और गोदामों व रद्दी कागज के स्टॉक केंद्रों पर छापे मारकर अवैध जमाखोरी पर नियंत्रण की अपील की है। संगठन ने आगे कहा, 'कुछ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा देश में रद्दी कागज की कृत्रिम कमी का माहौल बनाने के दुष्प्रयास खत्म किये जाने चाहिए, जिससे कागज विनिर्माता और कागज उपभोक्ताओं पर अनावश्यक दबाव न पड़े।'

सर्फ एक्सेल का नवीनतम होली अभियान #रंग अच्छे है

अपने प्रियजनों के साथ जुड़ने की आज की भावनात्मक जरूरत को संबोधित करते हुए, अभियान होली के रंगों का उपयोग करके बनाए गए एक भावनात्मक बंधन की दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाता है। महामारी ने पिछले साल समाज के सभी वर्गों को अलग-थलग कर दिया था। इस बात ने हमें बहुत प्रभावित किया कि एक दूसरे के साथ हमारा सामाजिक और भावनात्मक संबंध क्या है। भले ही जीवन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा हो, लेकिन समाज के कुछ कमजोर वर्ग जैसे बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा के लिए सामाजिक रूप से दूर बने हुए हैं। और जब हम सभी अपने प्रियजनों के यहाँ जाना चाहते हैं, तो यात्रा और सामाजिकता से जुड़े जोखिमों को देखते हुए यह कठिन है। हमारे बुजुर्गों के लिए, इसका मतलब यह भी है कि वे लंबे समय से अपने परिवारों के करीब होने की भावनात्मक और सामाजिक गर्मजोशी से वंचित हैं। सर्फ एक्सेल का नवीनतम होली अभियान अपने अद्वितीय 'दाग अच्छे हैं' ब्रांड के प्रस्ताव को आगे बढ़ाता है और 'एकजुटता' के माध्यम के रूप में रंगों का उपयोग करना जारी रखता है। इस वर्ष, यह दिखाता है

कि होली के रंग शारीरिक दूरी के बावजूद भावनात्मक दूरी को पाटने और दिलों को करीब लाने में मदद कर सकते हैं। सर्फ एक्सेल का नवीनतम अभियान #रंग अच्छे है एक मासूम लड़के द्वारा दिल को आनन्दित करने वाला इशारा दिखाता है जो होली के उत्सव में अपने दोस्त रैंचो, एक बुजुर्ग पड़ोसी को शामिल करना चाहता है। यह महसूस करने पर कि रैंचो को हर किसी की तरह उत्सव में शामिल नहीं किया जा सकता है, वह रैंचो के साथ अपने स्वयं के उत्सव का फैसला करता है। टीवीसी भावनात्मक भागफल का निर्माण करता है जैसा कि लड़का कहता है, 'मेरे हाथ नहीं पहुंचेंगे, इसलिए रंग पहुंचा दिए।' लड़के की सादगी और रैंचो के प्रति उसकी सहानुभूति होली की सच्ची भावना को जीवंत करती है और प्रदर्शित करती है कि भौतिक दूरी को भावनात्मक संबंधों को नहीं बदलना चाहिए, इस तथ्य को विज्ञापन में दिखाया गया है। अभियान के शुभारंभ पर टिप्पणी करते हुए, प्रभा नरसिम्हन, कार्यकारी निदेशक और वीपी - होम केयर, साउथ एशिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने कहा, 'होली हमारे देश में सबसे बड़े और सबसे प्रिय त्योहारों में से एक है और पिछले दो वर्षों में हमारे होली अभियानों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों के साथ मजबूत भावनात्मक जुड़ाव बनाने में सक्षम हैं। यह वर्ष थोड़ा अलग है क्योंकि हम सभी अभी भी महामारी के प्रभावों से जूझ रहे हैं, जिसने शारीरिक और भावनात्मक दोनों दूरी बनाई है। जनसंख्या के संवेदनशील खंड की भावनात्मक जरूरतों को संबोधित करते हुए, विज्ञापन दिखाता है कि एक युवा लड़का उत्सव के उत्सव में बुजुर्गों को शामिल करने का प्रयास करता है। यह 'दाग अचे हैं' के हमारे ब्रांड दर्शन का एक स्वाभाविक विस्तार है, जिसमें हमने हमेशा अच्छे काम करते हुए और अच्छे मूल्यों का प्रदर्शन करते हुए बच्चों को गंदे होते हुए दिखाया है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग इस त्योहारों के मौसम में अपने परिवारों से जुड़ने के अपने अनोखे तरीके खोजने के लिए प्रेरित हों।'

इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट समस्या से निपटने के लिए

इंदौर में चलाया गया क्लीन टू ग्रीन कैम्पेन

124 स्कूल और कॉलेज, 31 आरडब्ल्यूए, 46 थोक उपभोक्ता और कार्यालय समूह, 10 अनौपचारिक क्षेत्र इकाइयाँ, और 31 डीलर और खुदरा विक्रेता शामिल

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

रिवर्स लॉजिस्टिक्स ग्रुप (आर एल जी) - व्यापक रिवर्स लॉजिस्टिक्स समाधानों की अग्रणी वैश्विक सेवा प्रदाता - ने मई 2020 में अपना प्रमुख अभियान 'क्लीन टू ग्रीन' लॉन्च किया था जो मार्च 2021 तक चलेगी। इस अभियान का उद्देश्य जिम्मेदार संगठनों के साथ भागीदारी करके इलेक्ट्रॉनिक्स के जिम्मेदार निपटान और रीसाइक्लिंग के लिए सुरक्षित प्रथाओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करना है।

भारत वर्तमान में दुनिया में ई-कचरे का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है जो सालाना 2 मिलियन टन ई-कचरे का उत्पादन करता है, हालांकि केवल 0 .036 मिलियन टन कचरे का प्रसंस्करण किया गया था। भारत में लगभग 95 प्रतिशत ई-कचरे का अनौपचारिक क्षेत्र में कच्चे तरीके से पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। आरएलजी के क्लीन टू ग्रीन अभियान को पिछले 3 वर्षों में बड़ी सफलता मिली; 25 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में, स्कूल, कॉलेज, आरडब्ल्यूए, ऑफिस क्लस्टर्स, रिटेलर्स, थोक उपभोक्ता और अनौपचारिक क्षेत्र में हितधारकों तक पहुंच बढ़ी । पूरे भारत में कुल 2,210 गतिविधियाँ आयोजित की गईं, यह अभियान 22,21,406 व्यक्तियों तक पहुँचा। आरएलजी इंडिया से जुड़े निर्माता / ब्रांड माइक्रोसॉफ्ट, एलजी, लेनोवो, पायनियर, मोटोरोला, ब्रदर, सीमेंस, आईएफबी, हायर, हैवल्स, लॉयड्स, गोदरेज, वीडियोजेट, वीडियोटेक्स, टेक्सलाविज़न, डेजवा, शिंको, इनफिनिक्स, टेक्नो, इटेल और ओरिमो हैं ।अभियान ई-कचरे के सुरक्षित निपटान को बढ़ावा देने में उनके साथ सक्रिय रूप से काम करेगा। क्लीन टू ग्रीन कैम्पेन के तहत इंदौर शहर के आरडब्ल्यूए, अनौपचारिक क्षेत्र, कॉलेज, कार्यालय समूह और रिटेल में 120000 से अधिक लोगों को ई-वेस्ट हैंडलिंग और डिस्पोसल के बारे में प्रशिक्षित किया गया ।

क्लीन टू ग्रीन अभियान के बारे में बोलते हुए सुश्री राधिका कालिया, प्रबंध निदेशक, आरएलजी इंडिया ने कहा, 'पिछले 3 वर्षों में हमारे अभियान को मिली सफलता से हम प्रोत्साहित हुए। वित्त वर्ष 2019-20 में, हमने क्लीन टू ग्रीन अभियान की पहुंच का विस्तार यह सुनिश्चित करने के लिए किया कि व्यक्तियों और पेशेवरों में यह समझ बढे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का उचित निपटान और रीसाइक्लिंग एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है और जनता के बीच ई-कचरे के जिम्मेदार निपटान के बारे में जागरूकता की कमी गंभीर मुद्दा है।' अभियान के दूसरे वर्ष के शुभारंभ में बोलते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निदेशक डॉ। संदीप चटर्जी ने कहा, 'क्लीन टू ग्रीन अभियान ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और कॉर्पोरेट निकायों के साथ भारत में ई-कचरे के जिम्मेदार निपटान और पुनर्चक्रण सुनिश्चित करने के लिए सहयोग किया है । इस अभिनव और व्यापक समाधान ने निर्माताओं और वितरकों से उत्पादों की वापसी को प्रेरित किया और उपयोग के कई चक्रों को सुविधाजनक बनाया। भारत में ई-कचरा प्रबंधन को चलाने के लिए ऐसी पहल की आवश्यकता है।'

प्लास्टिक उद्योग के आईपीपीएफ क्रिकेट लीग में हुए रोमांचक मुकाबलें

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

कोरोन काल ने बीते 1 वर्ष में आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी रोक दिया है। उद्योगों में छाई निराशा और मंदी के बीच खेल के माध्यम से उद्योगपतियों को जोडने और प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस स्पर्धा के माधयम से स्वचछता का संदेश देने के लिए इंदौर नगर पालिक निगम को 5 हजार प्लास्टिक डस्टबिन भेंट करने का कार्य भी किया जाएगा।

मप्र में प्लास्टिक उद्योगों के सबसे बडे संगठन इंडियन प्लास्टिक फोरम ने प्लास्टिक उद्योगों के उत्साहवर्धन के लिए पहल करते हुए प्लास्टिक उद्योगों के बीच 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया। 5 से 7 मार्च के बीच संपन्न हुई इस स्पर्धा में विभिन्न प्लास्टिक ईकाइयों की 12 टीमों ने भाग लिया। ये टीमें 8 खिलाडी और 6 ओवर के थे। निपानिया स्थित प्लेयर कोर्ट पर हुए रोमांचक क्रिकेट मैचों में हर टीम ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया।

इंडियन प्लास्टपैक फोरम के अध्यक्ष श्री सचिन बंसल ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से अपने उद्योगों में सुबह से शाम तक लगे रहे वाले उद्योगपतियों को उनके संस्थान के ही कर्मचारियों के बीच से खिलाडी चुनने थे। ये सभी खिलाडी मशीन आपरेटर,

मैनेजर, सुपरवाईजर, पैकिंग या सप्लाय टीम के सदस्य थे। इस आयोजन को करने का उद्देश्य उद्योगों के बीच आपसी तालमेल और ऑफिसों से बाहर एक साथ मिलने का अवसर मिलें और खेल के माध्यम से सभी को प्रोत्सहित करना है।

इस स्पर्धा में 300 प्लास्टिक इकाइयों के बीच में 12 टीम बना कर क्रिकेट मैच खेला गया है। 3 दिवसीय इस स्पर्धा में प्लास्टिक व्यवयास से जुडें नाम पर टीम बनाई गई थी। फाइनल मुकाबला इंडियन प्लास्ट पैक फोरम और पोलिमर डिस्टीब्यूटर की टीम के बीच खेला गया। इस मुकाबलें में पोलिमर डिस्टीब्यूटर की टीम विजयी रही। विजेता टीम को 21 हजार रूपए का पुरस्कार दिया गया। रनर अप टीम को 11 हजार की राशि मिली। आयोजन को बैक क्रियेशन और इंडियन प्लास्ट टाइम्स ने स्पांसर किया था ।

आसुस ने भारत में टीयूएफ डैश एफ 15 गेमिंग लैपटॉप के लॉन्च के साथ अपनी टीयूएफ सीरीज़ को मजबूती प्रदान की

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

प्रमुख ताइवानी टेक कंपनी, आसुस इंडिया ने अपने सुपर स्लिम 15-इंच डिवाइस, नए टीयूएफ डैश एफ 15, के लॉन्च की घोषणा के साथ भारत के अपने टीयूएफ लैपटॉप पोर्टफोलियो का विस्तार किया। पतली एवं हल्की डिजाइन में उपलब्ध, टीयूएफ डैश एफ 15 में पोर्टेबिलिटी है। यूजर्स को कहीं भी गेमिंग, काम करने और कहीं भी उत्पादक रहने की क्षमता के साथ सशक्त बनाने के लिए तैयार किये गये, नये आसुस लैपटॉप में अपराजेय परफॉरमेंस के लिए नवीनतम 11वीं जनरेशन इंटेलरु कोररू आई7-11370एच प्रोसेसर के साथ जेफोर्स आरटीएक्सरू 3070/3060 जीपीयू है। लैपटॉप की लॉन्चिंग सीईएस 2021 के वर्चुअल सम्मेलन के दौरान विश्व स्तर पर किया गया और यह अब भारत में अपनी पहचान बनाने के लिए उपलब्ध है। इसका शक्तिशाली कोर एक्सपीरियंस हाईएंड सुविधाओं से सुसज्जित है, जो आमतौर पर सुलभ मूल्य पर उपलब्ध नहीं होता है, जैसे कि टूर्नामेंट लेवल गेमिंग पैनल, जिसमें 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, बहुमुखी थंडरबोल्टरू 4 पोर्ट और टू-वे एआई पॉइज कैन्सिलेशन टेक्नोलॉजी शामिल है। इसमें 16.6 घंटे की वीडियो प्लेबैक और विभिन्न प्रकार के एडाप्टर्स और पॉवर पैक्स के लिए बैटरी लाइफ प्रदान करने वाली टाइप-सी चार्जिंग की सुविधा है। लॉन्च के बारे में बताते हुए, अर्नोल्ड सु, बिजनेस हेड, कंज्यूमर एंड गेमिंग पीसी, सिस्टम बिज़नेस ग्रुप, आसुस इंडिया ने कहा कि 'हमारा लक्ष्य अपने उपभोक्ताओं को उन उत्पादों को उपलब्ध कराना है जो उद्योग-अग्रणी टेक्नोलॉजी के साथ उनके परफॉरमेंस को बढ़ाते हुए उन्हें सशक्त बनाये। हमारी टीयूएफ गेमिंग सीरीज़ इसका समर्थन करती है और इसे सभी के लिए सुलभ बनाकर गेमिंग अनुभव को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 11 वीं जेनरेशन के इंटेलरु कोर प्रोसेसर से संचालित, टीयूएफ डैश एफ 15 सभी नये अनुभव देने और भारत के बाजार में नई उपलब्धियां हासिल करते हुए, सीरीज़ की सफलता को दोहराने के लिए तैयार है। हमारा जोर उपभोक्ता की आवश्यकताओं को विकसित करने पर रहता है और हम अपनी उत्पाद विकास रणनीति बनाते हुए उपभेक्ता को केंद्र में रखते हैं, और अपनी नवीनतम पेशकश के साथ हमारा अगला लक्ष्य उनके गेमिंग अनुभव को बढ़ाना है।' राहुल मल्होत्रा, डायरेक्टर –कंज्यूमर सेल्स, इंटेल इंडिया ने कहा कि '11वीं जेनरेशन के इंटेल कोर एच-सीरीज़ मोबाइल प्रोसेसर की नई लाइन अल्ट्रापोर्टेबल फॉर्म फैक्टर्स में इंथुजियास्ट-लेवल की गेमिंग के लिए संभव सीमाओं को बढ़ाता है। परफॉरमेंस और स्लीक डिजाइन का यह कॉम्बिनेशन उस व्यक्ति के लिए बनाया गया है, जिसे ऐसे लैपटॉप की जरूरत है जिसे कहीं भी ले जाया जा सके और वह सारे काम कर सके।'

आईएसी ने कहा- महंगे पेट्रोल डीजल के बीच वाहन एलपीजी 40% सस्ता विकल्प

नई दिल्ली। एजेंसी

पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों के बीच ग्राहक वाहन एलपीजी का विकल्प चुन सकते हैं। इंडियन ऑटो-एलपीजी कोलिशन (आईएसी) ने मंगलवार को यह सुझाव दिया। आईएसी का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की तुलना में एलपीजी ईंधन 40 प्रतिशत सस्ता बैठता है। देश के ऑटो एलपीजी आपूर्तिकर्ताओं के शीर्ष निकाय ने कहा कि उपभोक्ता आसानी से कन्वर्जन किट लगाकर अपने वाहनों को ऑटो एलपीजी में बदल सकते हैं। इससे उनके ईंधन बिल में उल्लेखनीय कमी आएगी।

आईएसी ने ऑटो एलपीजी/सीएनजी कन्वर्जन किट पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की 28 प्रतिशत की दर में कटौती की मांग की है। इससे ग्राहकों के लिए अपने वाहन में कन्वर्जन किट लगाना सुगम हो पाएगा। आईएसी ने बयान में कहा, ''पेट्रोल और डीजल का दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। ऐसे में उपभोक्ता सस्ते विकल्प की तलाश कर रहे हैं। ऑटो एलपीजी से उपभोक्ताओं का अपनी ईंधन की लागत में अच्छी-खासी बचत करने में मदद मिलेगी।''

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित । संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।